निरीक्षण टीम व स्वास्थ्य मंत्री की आगमन नौटंकी से अस्पताल अधिकारी हुए 'चौकन्ने'

फ़रीदाबाद (म.मो.) बल्लबगढ़ सेक्टर तीन स्थित एफआरयू (प्रथम रेफरल यूनिट) का निरीक्षण करने वाली एनक्यूएएस (नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड) की टीम के आगमन की सूचना पाकर यूनिट के अधिकारी डॉक्टर मान सिंह चौकन्ने हो गए हैं। उन्होंने अपने स्टाफ़ को आगाह किया है कि 20-22 जुलाई तक काम से कभी भी गैरहाजिर न रहें, सफ़ाई का पूरा ध्यान रखें, दवाईयों आदि का पूरा इंतजाम रखें तथा आवश्यक स्थानों पर साइनेज आदि को ठीक से लगा कर रखें।

विदित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत करीब 25 वर्ष पूर्व इस यूनिट की स्थापना की गई थी। इसके लिये करीब डेढ एकड़ के भूखंड पर दो मंजिला इमारत तथा डॉक्टर व स्टाफ़ आदि के लिये रिहायशी मकान भी बनाये गये थे। इसका मुख्य उद्देश्य यह रखा गया था कि आस-पास की जनता के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें तथा गर्भवती मलिाओं की देख-भाल व डिलिवरी आदि की व्यवस्था करना था। लेकिन यह यूनिट दिखावे मात्र से आगे कभी बढ़ नहीं पाई। इतनी बड़ी इमारत व आवासीय भवन वर्षों तक खाली ही पड़े रहे। इसका मूल कारण यहां पर स्थायी स्टाफ़ की जगह ठेकेदारी का स्टाफ़ होना बताया जाता है।

जाहिर है कि ऐसे में न तो साधारण मरीज़ों की कभी देख-भाल हो पाई और न ही गर्भवती महिलाओं का यहां कुछ भला हो पाया। जलापूर्ति की उचित व्यवस्था न होने के चलते शौचालय की सफ़ाई की बात तो छोड़िये पीने तक का पानी यहां उपलब्ध नहीं हो पाता। साइनेज़ न होने के चलते नवागंतुक को पता ही नहीं चल पाता कि किस कमरे में क्या होना है, इसलिये वह इधर-उधर भटकता ही रह जाता है। आधे से अधिक स्टाफ़ फरलो पर ही रहता है। गत वर्ष यहां की इंचार्ज डॉक्टर शशि गांधी तो अमरपुर स्थित अपने खेतों पर काम करने के लिये भी यहीं से स्टाफ़ को भेजा करती थी। इस तरह के माहौल में दवाओं आदि की यहां से अपेक्षा करना ही बेमानी है।

इन्हीं सब बातों के मद्दे नज़र डॉक्टर मान सिंह ने अपने स्टाफ़ को समय पूर्व चेतावनी देकर सचेत किया है कि आने वाली निरीक्षण टीम के सामने बेहतर प्रदर्शन करके अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करें।

सवाल यह पैदा होता है कि निरीक्षण टीम आने के वक्त ही अधिकारी सचेत क्यों होते हैं, सदैव अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से क्यों नहीं निभाते? ड्यूटी भी कोई क्या निभाये, जितने डॉक्टरों व स्टाफ़ की स्वीकृति यहां के लिये की गई थी उसका एक चौथाई भी यहां कभी तैनात नहीं रहा। ऐसे में निरीक्षण टीम का यहां आना भी किसी नौटंकी से कम नहीं है।

सिविल सर्जन ने भी अपने स्टाफ़ को चेताया

विदित है कि भारतीय जनता पार्टी के तीन दिवसीय एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिये स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी फ़रीदाबाद पधार रहे हैं। दिनांक 15,16,17 यह तीन दिन उनके यहां रहने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता ने अपने आधीनस्थ ज़िले भर के तमाम छोटे-बड़े केन्द्रों को बाकायदा इस बाबत पत्र लिख कर सूचित किया है। पत्र में सभी केन्द्रों के इंचार्जों को आगाह किया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री कभी भी किसी भी केन्द्र पर छापामारी कर सकते हैं। इसलिये सभी कर्मचारी सावधान रहें, अपनी सीट न छोड़ें और सफ़ाई आदि का विशेष ध्यान रखें।

सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया उक्त सर्कुलर यह समझने के लिये पर्याप्त है कि ज़िले के तमाम स्वास्थ्य केन्द्रों में आये दिन क्या होता होगा? ये लोग केवल मंत्री के सम्भावित छापे के डर से ही अपना वह काम करते हैं जो उन्हें प्रति-दिन करना चाहिये।

सरकार ने विधायकों की सुरक्षा बढ़ाई, जनता बेशक लुटती-पिटती रहे

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

हरियाणा विधानसभा के 6 विधायकों-सोहना से भाजपा के संजय सिंह, सढ़ोरा से कांग्रेस की रेणु बाला, सोनीपत से सुरेन्द्र पवार, सफीदों से सुभाष गांगोली और बादली से कुलदीप वत्स व फिरोजपुर झिरका से मामन खान को धमकियां मिली तो सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय किया है। प्रत्येक विधायक की सुरक्षा के लिये चार-चार सशत्र पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। फिलहाल इनके पास अपेक्षाकृत हल्के हथियार रहते हैं जिनके स्थान पर बेहतर मारक क्षमता वाली एके-47 बंदूक दी जा रही है। इसके अलावा इन सुरक्षाकर्मियों को विधायकों के घरेलू काम करने से रोक कर बेहतर ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है।

विदित है कि अधिकांश सुरक्षाकर्मी विधायकों एवं मंत्रियों के घरेलू काम करते-करते उनके परिवारों में इस प्रकार घुल-मिल जाते हैं कि वर्षों-वर्षों तक वहीं जमे रह कर बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। नियमानुसार तीन से छः माह के बाद इन सुरक्षाकर्मियों का तबादला हो जाना चाहिये।

बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि किसी भी व्यक्ति के चुनाव जीतने यानी विधायक अथवा मंत्री बनने पर उसकी जान को खतरा क्यों हो जाता है? क्या वह चुनाव जीतने के बाद इतना अलोकप्रिय हो जाता है कि उसकी जान के लाले पड़ जाते हैं?

जाहिर है कि पदासीन होने के बाद ये राजनेता जिस तरह के जन विरोधी एवं लूट-मार के धंधे करते हैं, तरह-तरह के गिरोहों का पालन-पोषण करते हैं उसी के चलते ये लोग जनता में इतने बदनाम हो चुके होते हैं कि इनके अपने मतदाता ही इन्हें दुश्मन नज़र आने लगते हैं। चुनावी वायदे भूल कर जनप्रतिनिधि जब केवल अपना घर भरने में जुट जाता है तो लोकप्रियता कहां बचेगी? ऐसे में अपने ही लोगों के बीच जाने के लिये उन्हें पुलिस घेरे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन वे नहीं जानते कि जब जन आक्रोश उठेगा तो उसके सामने यह घेरा कभी नहीं टिक पाता।

विधायकों तथा उनके बल पर टिकी सरकार को अपनी सुरक्षा की तो बहुत चिंता है लेकिन आम जनता की सुरक्षा से उनका कोई लेना-देना नहीं। जिस तरह की धमकियां उक्त विधायकों को मिली बताते है उस तरह की न केवल धमकियां बल्कि वारदातें आम लोगों के साथ होना रोजमर्रा की बात हो गई है। सुरक्षा देना तो दूर की बात पुलिस आसानी से एफआईआर तक दर्ज नहीं करती।

पॉलीथीन बंद कराने की नौटंकी, छोटे दुकानदारों का उत्पीड़न

फ़रीदाबाद (म.मो.) जब कभी शासन-प्रशासन की नींद खुलती है तो वे कोई न कोई नया ड्रामा लेकर आ खड़े होते हैं। करीब आठ-दस साल पहले भी पॉलीथीन की थैलियां बंद कराने के आदेश प्रशासन द्वारा दिये गये थे। इन आदेशों के बल पर सरकारी कर्मचारियों ने रेहड़ी, फ़ड़ी, व छोटे दुकानदारों को जमकर रगड़ा लगाया था। अनेकों के मोटे-मोटे चालान किये गये थे तो अनेकों से चालान न करने के एवज में रिश्वतें ली गई थी। वही सिलसिला इस माह से पुनः चालू हो चुका है।

सवाल यह पैदा होता है कि सब्जी आदि को पॉलीथीन में डालकर देने वाले छोटे-मोटे दुकानदारों पर तो सरकार कानून का डंडा चला रही है, परन्तु पॉलीथीन की थैलियों में दूध बेचने वाली कम्पनियों, चिप्स व तरह-तरह की नमकीन को पैकेटों में बेचने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा गुटका-तम्बाकू आदि को ऐसे ही पैकेटों में बेचने वाली फिल्मी हीरो कम्पनियों से सरकार क्यों घबराती है? क्या इन कंपनियों द्वारा बनाये गये पैकेट आसानी से नश्वर होने वाले पदार्थ से बने हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी किसी अन्य पॉलीथीन पदार्थ की तरह अनश्वर होते हैं।

यदि सरकार वास्तव में ही पर्यावरण के प्रति गंभीर है तो इसके नाम पर तरह-तरह की नौटंकियां न करके इस दिशा में गंभीर कदम उठाये। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि पॉलीथीन से पर्यावरण को भयंकर क्षति पहुंच रही है। इस क्षति से बचने के लिये सरकार को छुट-मुट दुकानदारों से दो-चार होने की बजाय उन कारखानों व उत्पादों को ही बंद कर देना चाहिये जहां पर इनका उत्पादन और माल तैयार होता है। लेकिन सरकार ऐसा कभी करने वाली है नहीं। करे भी क्यों, जब ड्रामेबाज़ी से ही काम चल रहा है।